



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ६, अंक ७(२)]

बुधवार, जून ११, २०१४/ज्येष्ठ २१, शके १९३६

[पृष्ठ ५, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २५

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानपरिषद में दिनांक ११ जून २०१४ ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम ११३ के अधीन प्रकाशित किया जाता है :-

L. C. BILL No. XI OF 2014.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA FOREST PRODUCE
(REGULATION OF TRADE) ACT, 1969.

विधानपरिषद का विधेयक क्रमांक ११ सन् २०१४।

महाराष्ट्र वन-उपज (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, १९६९ में संशोधन संबंधी विधेयक।

सन् १९६९ **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र वन-उपज (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, १९६९ का महा. ५७। में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के पैसठवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है, :-

१. (एक) यह अधिनियम, महाराष्ट्र वन-उपज (व्यापार का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, २०१४ संक्षिप्त नाम कहलाए। और प्रारंभ।

(दो) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

(१)

सन् १९६९ का
महा. ५७ की धारा
२ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र वन-उपज (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, १९६९ जिसे इसमें आगे “मूल अधिनियम” सन् १९६९
कहा गया है) की धारा २ में, खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :— का महा.
५७।

(ज ज) “ग्राम वन प्रबंधन समिति” का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य में यथाप्रयुक्त भारतीय वन अधिनियम, १९२७ और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन, ग्राम वन के रूप में किसी भी ग्राम समूह या ग्राम पंचायत का इस निमित्त जारी किए गए राज्य सरकार के आदेश द्वारा समनुदेशित किया गया है जहाँ सरकार का अधिकार उस या किसी भूमि पर है जो संरक्षित वन के रूप में गठित की गई या संरक्षित वन जानेवाले किसी भाग का प्रबंधन और संरक्षण करने के लिए महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा ४९ के अधीन गठित की गई संयुक्त वन प्रबंधन समिति या कोई ऐसी समिति चाहे जो भी नाम हो, उससे हैं ;”।

सन् १९५९ का
महा. ५७ की धारा
३ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु, ग्राम वन प्रबंधन समितियों को निशान लगाए गए या समनुदेशित किए क्षेत्र महाराष्ट्र वन उपज (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, २०१४ के प्रारंभण की दिनांक से ऐसे इकाईयों (युनिटों) से अपवर्जित किये जायेंगे।

सन् १९६९ का
महा. ५७ की धारा
५ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ५ में, उप-धारा (२) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

“(२क) उप धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ग्राम वन प्रबंधन समिति भारतीय वन अधिनियम, १९२७ के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अध्वधीन निशान लगाए या उसे समनुदेशित किए गए क्षेत्रों से संग्रहित वन उपज के परिवहन करने और संचय करने की हकदार होंगी।

सन् १९६९ का
महा. ५७ की धारा
६ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा ६ में, उप-धारा १ में, विद्यमान परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु, आगे यह कि संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा की गई शिफारिश के अनुसार, एक सदस्य ग्राम वन प्रबंधन समिति का प्रतिनिधि होगा।

सन् १९६९ का
महा. ५७ की धारा
७ में संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा ७ में, द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु, यह भी कि निशान लगाए गए ग्राम वन प्रबंधन समिति को नियत किए गए क्षेत्रों से संग्रहित की गई वन उपज के लिए ग्राम वन प्रबंधन समिति द्वारा किमत नियत की जाएगी और इस धारा के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन समेत, किमत नियत करने के लिए लागू होंगे।”।

सन् १९६९ का
महा. ५७ की धारा
८ में संशोधन।

७. मूल अधिनियम की धारा ८ में, निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु, निशान लगाए गए समनुदेशित किये गये ग्राम वन प्रबंधन समिति के क्षेत्रों से संग्रहित की गई वन उपजों के लिए, ऐसे डिपो का स्थान ऐसी समिति द्वारा नियत किया जाएगा और कामकाज के घंटे सुप्रकट रूप से सूचना पट पर प्रयोजन के लिए ऐसे सभी डिपों पर प्रदर्शित किए जाए।

सन् १९६९ का
महा. ५७ की धारा
९ में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा ९ में,—

“(क) उप धारा (१) में, विद्यमान परंतुक के बाद, निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु, आगे यह कि, ग्राम वन प्रबंधन समिति ऐसी समिति द्वारा नियत की गई किमत पर, निशान लगाये गये या समनुदेशित किये गये क्षेत्र से संग्रहीत वन उपज खरीद सकती है और समिति निशान लगाये गये या समनुदेशित किये गये क्षेत्र से संग्रहीत वन उपज से अन्य से वन उपज खरीदने के लिए सक्षम नहीं होगी।”

(ख) पार्श्व टिप्पणी में “ या एजेंट ” शब्दों के बाद, “ या ग्राम वन प्रबंधन समिति ” शब्द निविष्ट किए जाएँगे ।

९. मूल अधिनियम की धारा १० के लिए निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

सन् १९६९ का
महा. ५७ की धारा
१० में संशोधन ।

“ परंतु, ग्राम वन प्रबंधन समिति को स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करने की आवश्यकता नहीं होगी ।”

१०. मूल अधिनियम की धारा १२ के लिए निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

सन् १९६९ का
महा. ५७ की धारा
१२ में संशोधन ।

“ परंतु, ग्राम वन के समनुदेशित करने के राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किए गए निर्बंधनों और शर्तों के अधीन, ग्राम वन प्रबंधन समिति द्वारा खरीदी गई या संग्रहीत की गई कोई वन उपज जैसे उचित समझे ऐसी रीत्यामें बेचेगी या से अन्यथा व्यवस्था करेगी ।” ।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र वन उपज (व्यापार का विनियम) अधिनियम, १९६९ महाराष्ट्र राज्य में ऐसे व्यापार और उसके साथ जुड़े हुए मामले के लिए राज्य एकाधिकार के सृजन द्वारा कतिपय वन उपज के व्यापार के सार्वजनिक हित में विनियमन करने के लिए उपबंध करता है। महाराष्ट्र राज्य को यथाप्रयुक्त भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (सन १९२७ का १६) की धारा २८ की उप-धारा-१ के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम के अधिन स्थापित ग्राम-समुदाय, ग्रामपंचायत या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ का महा. २४) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत मानी गई सहकारी संस्था को समनुदेशित करेगी, जहाँ सरकार का अधिकार उस या किसी भूमिपर है, जो संरक्षित वन के रूप में गठित किया गया है या संरक्षित वनों के रूप में कहा गया है, या ऐसा समनुदेशन रद्द करना और इसप्रकार समनुदेशित सभी वन है तो वह “ग्राम-वन” कहा जाएगा। उक्त धारा २८ की उप-धारा २ के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार, ग्राम वनों के प्रबंधन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है, शर्तों को विहित करेगी जिसके अधीन समुदाय, पंचायत या संस्था को जिसे कोई अन्य समनुदेशन, टिंबर या अन्य वन उपज चराऊ भूमि उपबंधित किया गया है और ऐसे वनों का संरक्षण और सुधार करना उनके कर्तव्य होंगे।

२. महाराष्ट्र सरकारने दिनांक १३ मई २०१४ की भारतीय वन (महाराष्ट्र) (ग्राम वनों का समनुदेशन, प्रबंधन और रद्दकरण का विनियमन) नियम, २०१४ बनाया था, जिसमें, महाराष्ट्र राज्य को यथाप्रयुक्त भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (सन १९२७ का अधिनियम क्रमांक १६) की धाराओं २६, २८, ३०, ३२, ३४ और ७६ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना है। उक्त नियमों का कार्यान्वयन सुकर बनाने के लिए महाराष्ट्र वन उपज (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, १९६९ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर समझा गया है। इसमें मुख्यतः निम्न प्रस्तावित है,—

(क) उक्त अधिनियम के उपबंधों से ग्राम वन प्रबंधन समिति को निशान लगाए गए या समनुदेशित किए गए ग्राम वनों के क्षेत्र को अपवर्जित करना ;

(ख) उक्त समिती को निशान लगाए गए या समनुदेशित किए गए क्षेत्र से संग्रहित वन उपज का परिवहन और संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करना ;

(ग) उक्त अधिनियम की धारा ६ के अधीन गठित सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में उक्त समिती का एक सदस्य सहयोजित करना ;

(घ) निशान लगाए गए या समनुदेशित किए गए क्षेत्र से संग्रहित वन उपज की कीमत नियत करने के लिए उक्त समिती को सशक्त करना ;

(ङ) निशान लगाए गए या समनुदेशित किए गए क्षेत्र से संग्रहित वन उपज के संबंधि डिपो का स्थान और डिपो के कामकाजी घंटों को नियत करने के लिए उक्त समिती को सशक्त करना ;

(च) निशान लगाए गए या समनुदेशित किए गए क्षेत्र से संग्रहित वन उपज की खरीद करने के लिए उक्त समिती को सशक्त करना ; और

(छ) उक्त अधिनियम में अन्य परिणामिक संशोधनों को बनाना ।

इसलिए, सरकार महाराष्ट्र वन उपज (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, १९६९ धाराएँ २, ३, ५, ६, ७, ८, ९, १० और १२ में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है ।

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है ।

मुंबई,
दिनांकित ९ जून २०१४।

पतंगराव कदम,
वन मंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ निम्न प्रस्ताव अंतर्गृहीत है, अर्थात् :—

खंड १(२) इस खंड के अधीन, राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, जिस दिनांक को यह अधिनियम प्रवृत्त होगा वह दिनांक नियत करने की शक्ति प्रदान की गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपर उल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप का है।

(यथार्थ अनुवाद)

ललिता शि. देठे,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधानभवन :

मुंबई,

दिनांकित ११ जून २०१४।

डॉ. अनंत कळसे,

प्रधान सचिव,

महाराष्ट्र विधानपरिषद।